शिक्षा व्यवस्था की जानलेवा लापरवाही

तेलंगाना शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के एक सप्ताह में कई छात्रों की आत्महत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जान देने वाले कई छात्रों में ऐसे हैं, जो अच्छे नंबर से पास हुए थे, मगर तकनीकी खराबी के चलते फेल कर दिए गए। हम कहते जरूर है कि एक बार की असफलता से जीवन नहीं रुक जाता, मगर जब शिक्षा व्यवस्था ही संदेह के घेरे में हो, तो काम कैसे चलेगा।

हाल ही में तेलंगाना शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। अफसोस यह है कि नतीजे आने के एक सप्ताह भर बाद भी छात्रों की आत्महत्या के मामले नहीं रुक रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा में फेल होने के कारण पिछले एक सप्ताह में तेलंगाना राज्य में कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है। अब तक आत्महत्या के 18 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले चार साल में इंटर के नतीजे आने के बाद बच्चों की आत्महत्या के ये सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले साल भी 2018 में छह छात्रों ने नतीजे आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। अफसोसजनक यह है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। बिना सही तरीके से जांचे बिना नतीजे जारी करने के कारण भी विद्यार्थी अवसाद में जा रहे हैं और आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा दी थी लेकिन नतीजों में उन्हें अनुपस्थित दिखा दिया गया है।

कुछ छात्रों की शिकायत है कि 11वीं कक्षा में तो उनके बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन 12वीं में उन्हीं विषयों में उन्हें नाममात्र के अंक मिले हैं। कुछ अंक सूचियां तो ऐसी हैं, जिनमें विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण बताया गया है, लेकिन उन्हें अंक पास होने की आवश्यकता से कहीं ज्यादा मिले हैं। बच्चों की आशंकाएं बेवजह भी नहीं हैं। तेलंगाना राज्य के मनचेरियल इलाके की एक छात्रा को एक विषय में शून्य अंक दिए गए हैं, जबकि बीते साल यही छात्रा पूरे जिले में अव्वल आई थी। इस छात्रा की कॉपी दोबारा जांची गई तो उसके सौ में से 99 अंक आए। ऐसे वाकयों को देखते हुए सरकार ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। साथ ही सरकार ने भी माना है कि मूल्यांकन में चूक हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के अधिकारियों की लापरवाही छात्रों का भविष्य तो बिगाड़ ही रही है, जानलेवा भी साबित हो रही है। देश में हर साल परीक्षा परिणामों के समय देश एक कोने-कोने से बच्चों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। कभी मन-मुताबिक अंक न मिलने पर तो कभी अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के बोझ तले दबे बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम बनाने में हुई लापरवाही के चलते इतने सारे बच्चों का जीवन से हार जाना बेहद तकलीफदेह है। गौरतलब है कि तेलंगाना राज्य में इस साल 9.74 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 3.50 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार ने इस साल परीक्षा के नामांकन और परिणामों के लिए एक निजी फर्म ग्लोबरेना टेक्नलॉजीज से अनुबंध किया था। बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियां होने के कारण परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी हुई है। बच्चों और अभिभावकों के मुताबिक फर्म ने हजारों बच्चों को फेल किया है। कई बच्चों को परीक्षा देने के बावजूद अनुपस्थित दिखाया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि परीक्षा परिणामों की यही अनियमितता बच्चों का जीवन लील गई और कितने ही विद्यार्थियों की जिंदगी तकनीकी खामी की भेंट तक चढ़ गई।

चिंतनीय है राज्य प्रशासन की घोर लापरवाही के ऐसे मामले तकरीबन हर राज्य में होते हैं। हर साल होते हैं। देखने में आता है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाने पर विद्यार्थियों के अंक बढ़ ही जाते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर यह कोताही होती ही क्यों है? जबकि ऐसा होना हमारी शिक्षा व्यवस्था से बच्चों का भरोसा कम करने वाली बात है। विचारणीय है कि बच्चों का भविष्य संवारने वाली व्यवस्था की निष्पक्ष और न्यायोचित जवाबदेही के बिना परीक्षाओं या फिर परिणामों के मायने ही क्या हैं? दरअसल, ऐसी गलतियां हमारी शिक्षा व्यवस्था की लचरता और असंवेदनशीलता की बानगी हैं। इतना ही नहीं अंकों के खेल व अव्वल आने की रेस तक सिमटी हमारी शिक्षा व्यवस्था का बुनियादी उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए परीक्षा परिणामों में थोड़ी सी ऊंच-नीच होते ही बच्चे ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लेते हैं। असल में स्कूली शिक्षा प्रणाली का ध्येय तो यह होना चाहिए कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। अपने मनपसंद पाठ्यक्रम में आसानी से प्रवेश भी मिल सके।

जीवन से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करने और नैतिक रूप से दृढ़ बनने की सीख मिल सके। मेहनत और उचित मार्गदर्शन के बल पर उनका व्यक्तित्व निखारा-संवारा जा सके। आज की नई पीढ़ी विपरीत परिस्थितियों में पूरे धैर्य के साथ अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा कर सके, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी कमजोरी यही है कि यह न तो विद्यार्थियों को रोजगार या व्यवसाय के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाती है और न ही उन्हें नैतिक दृढ़ता देती है। मात्र अव्वल आने की दौड़ में परीक्षा परिणामों की जरा सी अनियमितता से वे खुद को जीवन में असफल समझने लगते हैं। अभिभावक भी ऐसे हालातों में संबल नहीं बनते बल्कि बच्चों से ही सवाल करते हैं। अकादमिक योग्यता के मापदंड ही बच्चों को जीवन के रण में सफल-असफल बनाते हैं। ऐसे में परीक्षा परिणामों में हुई गड़बड़ी के कारण परिणाम देखकर कई बच्चों ने खुद को जिंदगी में ही असफल मान लिया।

यह कटु सत्यहै कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बरसों से अनगिनत विसंगतियों से जूझ रही है। नतीजतन, कोई भी नया विचार, नीति या तकनीकी बदलाव पहले से मौजूद अव्यवस्था के भार तले ही दबकर रह जाते हैं। तकनीकी खामी के चलते रिजल्ट बनाने में हुई गलतियां भी कहीं न कहीं नए बदलाव को गंभीरता और जवाबदेही से न अपनाने का ही नतीजा है। हमारे शैक्षणिक ढांचे में तो परीक्षाएं ही अपने आप में तनावपूर्ण होती हैं। शिक्षण संस्थानों से लेकर सामाजिक परिवेश तक, बच्चों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बना रहता है, लेकिन तेलंगाना में जिन बच्चों के परीक्षा परिणाम अच्छे थे वे भी सिस्टम की लापरवाही के चलते जिंदगी से हार गए। अफसोस कि परीक्षा परिणामों के समय हमारे घरों में भी बच्चों को केवल उम्मीद भरी नजर से ही देखा जाता है। सफलता या असफलता की स्वीकार्यता को लेकर उन्हें मानसिक रूप से तैयार नहीं किया जाता। न ही घर के बड़े सदस्य इसके लिए तैयार होते हैं। बच्चों को यह दिलासा भी नहीं दिया जाता कि अंक चाहे जैसे आएं, हम तुम्हारे साथ हैं।

यही वजह है कि बच्चे रिजल्ट आने के समय तनाव और अवसाद में घिर जाते हैं। यही तनाव कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठाने की वजह बन जाता है। चिंतनीय है कि हमारे देश में 15 से 29 वर्ष के लोगों की आत्महत्या का दर सबसे अधिक है। ऐसे में जरूरी है अभिभावक सजग और सहयोगी बनें। साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी बच्चों के अनमोल जीवन को यूं अपनी लापरवाही की भेंट न चढ़ाए। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर व्यवस्था में ही खामी हो तो फिर बच्चों को दिलासा कैसे दें। उन्हें यह कैसे बताएं कि एक असफलता से जीवन नहीं रुक जाता। प्रशासन की लापरवाही से खराब हुआ परीक्षा परिणाम उन बच्चों के जीवन को कैसे लौटा पाएगा, जो इस दुनिया को विदा कह चुके हैं और उन परिवारों को कैसे दिलासा देंगे, जिनके घरों के चिराग अपनी विफलता से नहीं, बल्कि प्रशासन की लापरवाह के चलते सब कुछ खो चुके हैं। यह सच है कि तेलंगाना राज्य इस अव्यवस्था के दोषी अफसरों पर कार्रवाई करेगा और व्यवस्था सुधारने के दावे भी करेगा, मगर क्या आंख मिला पाएगा।

अनुज सक्सेना
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

सम्पादकीय

मोदी सरकार से 56 सवाल

वक्त के साथ दिन भी बदलते हैं और हालात भी। लेकिन शायद यह बात भारत में महिलाओं पर लागू नहीं होती। वर्ना आशादेवी को यह नहीं कहना पड़ता कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। भारत के जघन्यतम बलात्कारकांडों में एक था निर्भया कांड। वैसे तो बलात्कार की हर घटना जघन्य ही होती है, लेकिन कुछ प्रकरणों को अदालत रेयरेस्ट आफ द रेयर करार देती है, इसमें निर्भया कांड भी शामिल है। देश की राजधानी में हुए इस भयानक अपराध की गूंज विदेशों तक पहुंची थी। तब व्यापक पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुआ था और कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के खिलाफ माहौल बना था। भाजपा ने इस स्थिति का लाभ उठाया।

2014 के चुनाव में भाजपा ने नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। साथ ही महिलाओं की बेहतर स्थिति

का दावा भी किया। लेकिन निर्भया के माता-पिता पांच साल बाद भी निराश-हताश महसूस कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने वोट न देने का फैसला लिया है। बीबीसी से हुई एक विशेष बाातचीत में निर्भया की मां ने कहा कि- कहा जाता है कि वोट देना हमारा अधिकार है...तो हमारा भी तो अधिकार है कि हमें इंसाफ मिले। हमने पांच साल तक बड़े धैर्य से इंतजार किया। हमें भरोसा था कि हमें इंसाफ मिलेगा लेकिन अगर महिलाओं की दुर्गति देखें तो आज भी हम 2012 में खड़े हैं। आशा देवी निराश होकर कहती हैं- इतनी बच्चियां मर रही हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं। किसी को कोई फर्कनहीं पड़ता तो हमारे एक वोट न देने से उनको क्या पड़ेगा? उनके इस बयान से सहमत न होने का कोई कारण नजर नहीं आता।

कठुआ, बिलासपुर, शिमला और अब अलवर जैसे कई मामले समाज को शर्मिंदा होने के अवसर दे रहे हैं। लेकिन मजाल है कि समाज के माथे पर शिकन आ जाए। मंदिर कहां बनेगा, किस धर्म के लोगों में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही, समाज तो ऐसे ही सवालों में उलझा हुआ है। अभी चुनावों में भी असल मुद्दों पर बात से ज्यादा जहरबुझे बयानों पर चर्चा हो रही है। यहां तक कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पर भी राजनीति हो रही है। हाल ही में अलवर में एक महिला अपने पति के सामने सामूहिक बलात्कार का शिकार बनी। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिशें भी अपराधियों ने की। दलित महिला के साथ हुए इस गैंगरेप को अब सियासी रंग दिया जा रहा है। भाजपा आरोप लगा रही है कि चुनाव के कारण इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, जबकि कांग्रेस सरकार का कहना है कि वह महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से राजनैतिक दलों को तो लाभ हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए दोनों ओर से हार है।